(ग) पिछले वर्ष (नवम्बर से जून) के वनस्पति घी के उत्पादन 6,69,917 मी. टन की तुलना में इस वर्ष (नवम्बर 1989 से जून, 1990 तक) वनस्पति घी का उत्पादन 6,25,666 मी. टन हुआ है। इस वर्ष तिलहन की कम फसल तथा आयात में की गई कटौती के कारण कीमतें ऊंची हुई हैं।

(घ) वनस्पति घी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं:--

(1) खाद्य तिलहनों तथा तेलों की स्टाक सीमाओं को निचले स्तर पर पुनर्स्थापित किया गया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक ऋणों के न्यूनतम अन्तर में वृद्धि की गई है।

(3) केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी विरोधी अभियान चलाने के लिए राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।

Proposal to connect Karur and Salem

1177. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government's consideration to connect Karur and Salem (via) Namakkal, Rasipuram by a B G. line between Salem and Bangalore via Dharmapuri and Hosur;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the distance reduced by this scheme connecting Karur directly with Salem and Bangalore?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

खाद्य वस्तुओं का आयात

1178. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में किन-किन खाद्य वस्तुओं की कमी है तथा इस कमी के क्या कारण हैं तथा सरकार इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या सरकार कुछ खाद्य पदार्थों की कमी पूरी करने के लिए उनका आयात करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का तथा कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है तथा इस कारण से चालू वर्ष में हमें कितने-कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा उठाना होगा ;

(ग) क्या सरकार देश में खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी समाप्त करने के लिए कोई सख्त कदम उठाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रकार ; और

(घ) क्या सरकार ने कालाबाजारी समाप्त करने के लिए पिछले तीन महीनों के दौरान किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कोई मामले दर्ज किये हैं और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये है और मूल्य सूचकांक कितना नीचे आया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) चावल, गेहूं, चीनी आदि जैसी अधिकतर खाद्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। तथापि, मांग व आपूर्ति में अंतर होने के कारण खाद्य तेलों पर इस समय दबाव हैं। वर्ष 1990-91 के लिए खाद्य तेलों का आयात आगामी खरीफ मौसम के दौरान तिलहनों के उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी की बुराइयों को रोकने के लिए बनाए गए दो मुख्य कानून है। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों को लागू कर रहे हैं। उन्हें समय-समय पर सलाह दी गई हैं कि वे इन अधिनियमों को जोरदार ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाएं।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1990 के दौरान 30-7-1990 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए आदेशों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए 2718 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1921 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। 13 सप्ताह (28-4-90 से 28-7-90 तक) की अवधि के दौरान यद्यपि खाद्य तेलों, चावल, गेहूं, चना तथा अरहर के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि का रुख दिखाई दिया, तथापि, चाय, चीनी, आटा, मैदा, काली मिर्च तथा लाल मिर्च जैसी मदों के सूचकांकों में गिरावट का रुख दिखाई दिया।

Refusal for Registration by Employment Exchange, R. K. Puram

1179. SHRI JAGESH DESAI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, as reported by UNI in its despatches of July 4, 1990, that the Regional Employment Exchange Office at R. K. Puram in South Delhi had refused registration to hundreds of job seekers holding B.A. mark sheet certificates;

(b) what was the number of such job seekers who were declined registration; and

(c) what steps are being taken by Government to save unemployed youth from such harassment in the future?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) According to information received from Delhi Administration, no such candidate has been refused registration. To exercise a check on undue refusal, a system of issuing refusal slips indicating reasons for refusal has been introduced at employment exchanges. While the timings of registration have been increased to cope with rush of work instructions have also been issued to open additional registration counters.

Relaxation of Norms for Sugar Industry

1180. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an article on sugar industry which appeared in The Economic Times of 24th July describing the Government's decision to grant licences for new capacity with diluted norms as arbitrary and politically motivated;

(b) whether it is a fact there are already 400 sugar mills in operation with another 100 mills in the pipeline, and modernisation and expansion programmes in progress, resulting in a capacity of 160 lakh tons per annum which is the targetted production capacity for 2000 AD; and

(c) if so, what are the reasons for granting new licences especially with diluted norms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) There are 396 installed sugar factories in the country as on 31-7-1990. During the Seventh Five Year Plan Period after the announcement of the policy guidelines on 2-1-1987, Letters of Intent have been issued to 93 sugar factories for setting up of new units and to 150 factories for carrying out expansion in their existing capacity. As a result of the above, the total licensed capacity would be 158.59 lakh tonnes as on 31-7-1990 as against the targetted installed pro-